

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी - सर्वेश शर्मा R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 28/2025

दायर तारीख :- 15.04.2025

1. केसरी पुत्री नारायण पत्नी रामलाल
2. गणेश यादव पुत्र श्री नारायण
3. गोपाली पुत्री श्री नारायण
4. पतासी देवी पुत्री श्री नारायण
5. नानूराम यादव पुत्र श्री नारायण
6. रूपनारायण यादव पुत्र श्री नारायण
7. शांति देवी पुत्री श्री नारायण
8. सुखदेव यादव पुत्र श्री नारायण
9. संज्या देवी पुत्री श्री नारायण
10. छोटी देवी पत्नी श्री नारायण

समस्त जाति यादव नि० इन्दोकिया तहसील जयपुर जिला जयपुर राज०

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र श्रीराम उर्फ श्रीकिशन
2. कैलाश पुत्र श्रीराम उर्फ श्रीकिशन
3. रामदेव पुत्र बालूराम
4. हरदेव पुत्र बालूराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासी सुन्दरपुरा तहसील कि० रेनवाल
5. किशन कुमावत पुत्र श्यामलाल कुमावत निवासी प्लाट नम्बर 17 कान विहार गोविन्दपुरा झोटवाडा
6. पूनम कुमावत पत्नी शंकरलाल कुमावत निवासी मार्ग ए-4 कुमावत कालोनी खातीपुरा रोड झोटवाडा जयपुर
7. तहसीलदार तहसील कि०रेनवाल जिला जयपुर राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा

251-क की उप धारा (1)

उपस्थित :- श्री शंकरलाल काजला अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री लक्ष्मण सिंह , अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 1, 2
श्री योगेश शुक्ला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 26.09.2025

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनियम 1955 की धारा 251-क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजीयात खं०नं० 212/1, 212/2,215,216 कुल किता 4 कुल रकबा 3.4015 हैक्टेयर वाके ग्राम सुन्दरपुरा पटवार हल्का रामजीपुरा कला भू०अ०नि० मुण्डियागढ तहसील कि० रेनवाल जिल जयपुर राज० में प्रार्थीगण अपने पुख्ता मकान बनाकर निवास कर रहे है उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग के लिए उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिए पशुओं को लाने ले जाने के लिए आराजीयात की काश्त करने के लिए कृषि यंत्रों को लाने ले जाने के लिए अपनी फसल को मण्डी तक ले जाने के लिए तथा आवागमन के लिए पहले से रास्ता खसरा नम्बर 218 के पूर्वी-दक्षिणी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर मार्क ए बी सी से दर्शित 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी खसरा संख्या 218 रकबा 3.5027 हैक्टेयर में आपसी सहमति से वर्तमान में चालू मार्ग है जिसका प्रार्थीगण अपने जोत पर आने जाने के लिए बुजुर्गों के



अधिकारी
किशनगढ रेनवाल

समय से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को वर्तमान में अपने जोत के उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को वर्तमान में अपने जोत के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने के लिए 15 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण जो रास्ता विद्यमान है उसमें जब चाहे तब अवरोध उत्पन्न करते है। जो प्रार्थना पत्र में संलग्न नक्शा में मार्क ए0बी0सी0 से दर्शित किया गया है जो डामरीकृत रोड से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुंक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 218 के पूर्वी दक्षिणी सीमा की ओर से डामरीकृत रोड जो पूर्व से पश्चिम बनी हुई है और वर्तमान में आवागमन हेतु चालू है से जुड़ा हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरोधित करने पर प्रार्थीगण अपने कुए व मकान पर नही जा रहे है एवं जानवरों व कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में परेशानी उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के आवागमन के लिए उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शों में मार्क एबीसी से दर्शित उक्त रास्ते को 15 फुट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकर्ड में दर्ज कर प्रार्थी गण को अपने जोत पर आने जाने की सुविधा प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1,2 की ओर से वकील श्री लक्ष्मण सिंह ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रा0 पत्र पेश हुआ व अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 212/1, 212/2 वाके ग्राम सुन्दरपुरा में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 218 में जो रास्ता उत्तर दिशा की सीव के सहारे सहारे दिया गया था। उसकी अनुसार रास्ता चला आता रहा था किन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान व परेशान करने के लिए खसरा नम्बर 218 की सीव में दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जो रास्ता मार्क ए0बी0सी0 अपने नजरी नक्शा में बताया है वह गलत रूप से रास्ता लेना चाहता है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अपने जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थीगण स्पष्ट हाथो से न्यायालय में नहीं आये है प्रार्थीगण ने न्यायालय से तथ्यों को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजीयात में अपने जाने के लिए पूर्व से वैकल्पिक रास्ते बने हुये है। जो प्रार्थीगण ने जानबूझकर अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शों में नही दर्शाये गये है। खसरा नम्बर 218 की उत्तरी सीव पर सुविधाजनक व कम दूरी का रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थीगण जानबूझकर आते जाते नहीं है। तथा नया रास्ता कायम करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो कि खारिज किये जाने योग्य है तथा अब नया रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 218 के दक्षिण से उत्तर की तरफ मार्क ए0बी0सी0 कायम करवाना चाहते है जबकि यह रास्ता कभी नहीं रहा है इसी प्रकार प्रार्थीगण की आराजीयात में आने जाने का एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 217 की पूर्वी व खसरा नम्बर 214 की पश्चिमी सीव के सहारे सहारे बना हुआ है जिसमें से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 212/1, 212/2, 215, 216 में आते जाते है। लेकिन प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को नाजायज हैरान व परेशान करना चाहते है तथा प्रार्थीगण की आराजीयात में अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है तथा उनकी आराजीयात के टुकडे करवाना चाहते है तथा उनकी आराजीयात के टुकडे करवाना चाहता है तथा अप्रार्थीगण से रंजिश रखते हुए उनकी आराजीयात में रास्ता मार्क ए0बी0सी0 नया कायम करवाना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही ऐसा कोई रास्ता कभी प्रार्थीगण की भूमि में रहा है। प्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 215 व 216 आने जाने हेतु वर्तमान में वैकल्पिक रास्ते मौजूद है इसलिए जहां वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था प्रार्थीगण के पास हो तो उनको कोई रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 3 से 6 बावजूद सूचना हाजिर नही हुए अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर वकील योगेश शुक्ला ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश




 जिलाधिकारी
 जहानाबाद

किया है जिसका सूक्ष्मण विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि 218 की भूमि में से मार्क ए वी सी 15 फुट चौड़े रास्ते के आवागमन हेतु याचना की गई है। उक्त वादग्रस्त जमीन का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है तथा नहीं किररी प्रकार का सीमाज्ञान हो रखा है न किररी प्रकार की पत्थरगढी हो रखी है। नाही विभाजन नहीं हो रखा है। ऐसी रिथति में प्रार्थीगण को उक्त जमीन में से 15 फुट का रास्ता दिया जाना न्यायोचित्त नहीं होगा। प्रार्थीगण अपनी जमीन खसरा नम्बर 215, 216 में आने जाने हेतु सबसे नजदीक व सरल व वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 217 में उपलब्ध है उक्त जमीन में से ही वे आते जाते है तथा डामर रोड से भी खसरा नम्बर 217 व 214 की जमीन में से यदि रास्ता दिया जाता है तो वह सबसे नजदीक रास्ता होगा। जब तक खसरा नम्बर 218 की जमीन में विधिवत रूप से विभाजन, सीमाज्ञान नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का रास्ता नहीं दिया जाये तथा खसरा नम्बर 217, 214 की जमीन में कोई रास्ता दिया जाता है तो न्यायालय पक्षकारों को समुचित सुनवाई व जवाब देही का अवसर देकर आवागमन हेतु रास्ता दिये जाने हेतु विचार फरमाये।

3. अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार कि० रेनवाल द्वारा अपने पत्रांक भू०अ०/२०२५/२१६४ दिनांक ०७.०५.२०२५ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका सार इस प्रकार है। प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता है जो खातेदारी भूमि में से है। प्रार्थी के लिए अन्य कोई रिकोर्डमें रास्ता नहीं है। प्रार्थी के लिए रास्ता आवश्यकता है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित नहीं है। चाहे गये रास्ते की भूमि में खातेदार रामेदव पुत्र बालूराम जाति ब्राहमण ने एच०डी०एफ०सी० बैंक लि० के रहन दर्ज है व अन्य कोई खातेदार के रहन दर्ज नहीं है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि की डी०एल०सी० दर १०८२००० प्रति हैक्टैयर है। उक्त चाहे गये रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल ७८५ वर्गमीटर है। रास्ते की भूमि के खातेदारों को नोटिस देकर तामिल करवाया गया व उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

4. यहाँ पर हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम १९५५ की धारा २५१-ए का अवलोकन करना उचित समझते है। जो निम्नानुसार है।

251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. -

(1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, he order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such



उप-डिविजनल अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. धारा 251-ए के संबंध में काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जो निम्न अनुसार है।

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee: constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.




उपखण्ड अधिकाारी
किशनगढ़ रेन्वाल्स

6. हमने उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस पर मनन उपरांत एवं सुसंगत विधिक प्रावधान अनुसार कोई अभिधारी अन्य अभिधारी की जोत से होकर रास्ते के लिए आवेदन कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 218 में होकर रास्ता चाहा गया है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी की भूमि है। सुसंगत विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं की खातेदारी भूमि से रास्ता कायम करना धारा 251-ए के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा भी अन्य वैकल्पिक लघुत्तम रूट उपलब्ध है अतः केवल जोत की सुविधा उपभोग बाबत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने पर खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 26/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सर्वेश शर्मा) RAS
जयपुर न्यायालय
किरातगढ़-मेरवाड़ा